

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध बैंक प्रकरण संख्या 162 / 2023(GCMS : 2023/ 335)

बंधन बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम गृह फाईनेंस लिमिटेड), शाखा कार्यालय 44 के ब्लॉक,
टण्डन लेबोरेट्री के पास, श्रीगंगानगर

बनाम


1. साहब राम (मृतक) जरिये विधिक उत्तराधिकारी
(अ) सावित्री देवी (माता)
(ब) शिमला देवी (पत्नि)
(स) सलोनी (पुत्री)
(द) अरविन्द (पुत्र)



2. शिमला देवी पता कृष्णजी मंदिर के पास, ग्राम 59 एलएनपी (लालेवाला), तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335061 एवं अहाता नं. 38, श्री लिम्बा एग्री वर्क्स, पुलिस चौकी के पास, रिडमलसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर - 335061
3. चिमल लाल तावणियाँ पता ग्राम 60 एलएनपी, रिडमलसर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर - 335601
4. प्रवीण कुमार पता ग्राम 59 एलएनपी (लालेवाला), तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर-335061


06.12.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री संजय वर्मा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण साहबराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी सावित्री देवी, शिमला देवी, सलोनी देवी एवं शिमला देवी, चिमनलाल और प्रवीण कुमार सुविधा के रूप में दिनांक 21.09.2015 को खाता संख्या 20007060001338 में राशि 2.00/- लाख रुपये, दिनांक 21.09.2015 को खाता संख्या 20007060001348 में राशि 4.50/-लाख रुपये, दिनांक 14.05.2016 को खाता संख्या 20007060001490 में राशि 2.25/-लाख रुपये एवं दिनांक 14.05.2016 को ही खाता संख्या 20007060001509 में राशि 1.75/-लाख रुपये कुल 10.50/- लाख रुपये (अखरे रुपये दस लाख पचास हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक प्रदान की थी। ऋण सुरक्षा


जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

की एवज में अप्रार्थी साहबराम द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति अहाता संख्या 38, (क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट) ग्राम रिडमलसर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण साहबराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी सावित्री देवी, शिमला देवी, सलोनी देवी एवं शिमला देवी, चिमनलाल और प्रवीण कुमार को दिनांक 21.09.2015 को खाता संख्या 20007060001338 में राशि 2.00/-लाख रुपये, दिनांक 21.09.2015 को खाता संख्या 20007060001348 में राशि 4.50/-लाख रुपये, दिनांक 14.05.2016 को खाता संख्या 20007060001490 में राशि 2.25/-लाख रुपये एवं दिनांक 14.05.2016 को ही खाता संख्या 20007060001509 में राशि 1.75/-लाख रुपये कुल 10.50/-लाख रुपये (अखरे रुपये दस लाख पचास हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी साहबराम द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति अहाता संख्या 38, (क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट) ग्राम रिडमलसर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 03.02.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 22.05.2023 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.05.2023 को ही भिजवाये गये है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है किन्तु अप्रार्थी चिमनलाल को नोटिस प्राप्ति का ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।


जिला माजस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी साहबराम की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति अहाता संख्या 38, (क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट) ग्राम रिडमलसर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 22.05.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 22.05.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण साहबराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी सावित्री देवी, शिमला देवी, सलोनी देवी एवं शिमला देवी, चिमनलाल और प्रवीण कुमार को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 22.05.2023 भिजवाये गये है, धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप समस्त अप्रार्थीगण के पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार सतस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त नहीं हुए है।

Am
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते हैं तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है। समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है और प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस पुनः जारी किये बिना ही दो समाचार पत्रों में दिनांक 20.06.2023 को प्रकाशित करवाये हैं।

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Demand Notice

The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or**

[Signature]
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the branches of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand notice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 22.05.2023 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से समस्त अप्रार्थीगण को तामील नहीं हुई है और प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण की सम्पत्ति/निवास पर चस्पा किये बिना ही दिनांक 20.06.2023 को दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया है। जो **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002** के **RULE 3(4)** के प्रावधानों की अवहेलना है। इस प्रकार समस्त अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।


हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार की धारा 8 निम्नानुसार अवलोकनीय है :

पुरुष की दशा में उत्तराधिकारी के साधारण नियम : निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरुष की सम्पत्ति इस आधार पर उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यागत होगी:

(क) प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।

(ख) द्वितीयतः , यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है

.....



जिला मजिस्ट्रेट

श्री बंगानगर

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसकी माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि उसके उत्तराधिकारी की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकरण में मृतक साहबराम की मृत्यु के पश्चात उसके समस्त उत्तराधिकारियों रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था, परन्तु पत्रावली में समस्त उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया गया है अथवा नहीं?, इसके परिणामस्वरूप वारिसनामा या अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का प्रकरण संख्या डब्ल्यूपी नं. 27230/2009 अनवान् एस. सुहैना बानो वगै. बनाम इण्डियन बैंक, एआरएम ब्रांच वगै. निर्णय दिनांक 01.12.2010 अवलोकनीय है। उक्त पैटीशन संख्या 27230/2009 के निर्णय अनुसार मृतक ऋणी/गारंटर के वारिसान को धारा 13(2) का नोटिस उक्त नियम 2002 के नियम 3 के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 22.05.2023 अप्रार्थीगण साहबराम (मृतक) विधिक उत्तराधिकारी सावित्री देवी, शिमला देवी, सलोनी देवी एवं शिमला देवी, चिमनलाल और प्रवीण कुमार को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये हैं तथा अप्रार्थी ऋणी स्व.साहबराम के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है अथवा नहीं? के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे ये ज्ञात नहीं होता की प्रार्थी बैंक ने समस्त वारिसों को पक्षकार बनाया है। जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3** के तहत मान्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी स्व. साहबराम के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार न बनाकर एवं धारा 13(2) के नोटिस जारी न कर तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों की अवहेलना की है

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726 - State of Bihar & Anr versus Arvind Kumar & Anr के पैरा-13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये हैं :


जिला मजिस्ट्रेट
श्री बंगानगर

13. In *Manish Goel Vs Rohini Goel*, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that generally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see also : *Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors.*, (1997) 10 SCC 264; and *Karnataka State Road Transport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors*, AIR 2002 SC 629]

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बंधन बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 में अप्रार्थी ऋणी स्व. साहबराम के समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाये जाने अथवा न बनाये जाने का दस्तावेज पेश न करने के कारण, समस्त अप्रार्थीगण को तामील न होने के कारण और माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रार्थी बैंक का धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए धारा 13(2) के नोटिस सपडित नियम 3 की पालना करते हुए ऋणी के दस्तावेजों के अनुसार समस्त उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से करते हुए पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अंशुदीप)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर